पांच एक्सप्रेस-वे के लिए होगी हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था

यूपी के बजट में मिलेगी एक्सप्रेस-वे को रफ्तार

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

यूपी में बन रहे पांच एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट के काम को बजट के जरिए और रफ्तार देने की तैयारी है। चुनावी आहट तेज हो रही है। इसमें साल भर ही बचा है। योगी सरकार अपने चौथे बजट में इनके लिए हजारों करोड़ रुपये का बंदोबस्त करेगी ताकि इन परियोजनाओं को पंख लग जाएं।

औद्योगिक विकास, रोजगार व आर्थिक विकास के नजरिए से यह परियोजनाएं खासी अहम हैं। समय से इन्हें पूरा कराने के लिए जरूरी है कि पैसे की किल्लत न हो। इसीलिए इन्हें प्राथमिकता पर रखते हुए काम कराया जा रहा है। इस साल के पहले छह महीने में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भरने लगेंगे, वहीं मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी शुरू होना है। यूपी ऐसा राज्य है जहां एक साथ इतने एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है या शुरू होने वाला है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे , बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है।

इसके साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगे गाजीपुर से बलिया तक एक्सप्रेसवे की नई परियोजना भी जल्द शुरू होगी।

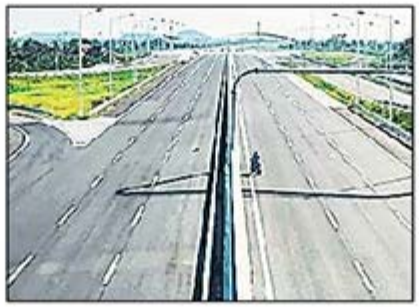

फिल्म सिटी व जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी रकम रखेंगे

योगी सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना फिल्म सिटी के शुरुआती काम के लिए बजटीय प्रबंधन होगा। इस परियोजना के लिए डीपीआर इसी महीने आने वाली है। इसके बाद इस पर डवलपर चयन कर आगे काम शुरू होना है। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण काम भी इसी साल आरंभ होगा। डिफेंस कारीडोर में जमीन खरीदने के लिए भी जरूरी रकम का इंतजाम बजट में किया जाएगा।

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने एक्सप्रेसवे व डिफेंस कारीडोर के लिए लगभग 9 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया था। इसी कारण एक्सप्रेसवे का काम कोरोना काल के बावजूद तेजी से आगे चलता रहा।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल भी चलना है। ऐसे में इसके लिए बजट में बड़ी रकम की दरकार है। जरूरत पड़ने पर बजट के बाद अगस्त सितंबर में अनुपूरक बजट लाकर रकम का इंतजाम होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे : इस एक्सप्रेसवे के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 लगभग 1855 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये का बंदोबस्त होगा। यह रकम एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने में खर्च होगी। यूपीडा हालांकि 2900 करोड़ रुपये हुडको से कर्ज भी लेगा। असल में जमीन खरीदने में करीब 10 हजार करोड़ रुपये चाहिए। सरकार ने 90 प्रतिशत जमीन जून तक खरीदने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में इस काम के लिए भारी रकम की जरूरत है।